RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 05 जुलाई से 11 जुलाई 2025 | भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 12 | अंक-48 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

भारत के शीर्ष उद्योगपतियों की संपत्ति में उछाल: सेंसेक्स से दोगुनी रफ्तार से बढ़ी नेटवर्थ

भोपाल: भारतीय शेयर बाजार ने पिछले एक साल में 7% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, लेकिन देश के शीर्ष 20 उद्योगपतियों की संपत्ति ने इसे कहीं पीछे छोड़ दिया है। इन उद्योगपतियों की कुल संपत्ति में औसतन 16% की वृद्धि हुई है, जो बाजार की वृद्धि दर से दोगुनी से भी अधिक है। इस दौरान कुछ उद्योगपतियों ने तो असाधारण वृद्धि हासिल की है, खासकर रक्षा और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में।

सत्यनारायण की संपत्ति में 78% की उछाल

रक्षा क्षेत्र में गोला-बारूद और ड्रोन निर्माण से जुड़ी कंपनी के मालिक सत्यनारायण ने इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। उनकी संपत्ति में 78% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा क्षेत्र में बढ़ती मांग और सरकारी पहलों जैसे 'मेक इन इंडिया' के कारण उनकी कंपनी को नए अनुबंध और निवेश प्राप्त हुए, जिसने उनकी नेटवर्थ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

बाजार की तुलना में तेज वृद्धि

सेंसेक्स ने पिछले 12 महीनों में 7% की वृद्धि हासिल की, जो एक स्थिर और सकारात्मक प्रदर्शन को दर्शाता है। हालांकि, शीर्ष उद्योगपतियों की संपत्ति में वृद्धि की रफ्तार बाजार से कहीं आगे रही। इसकी मुख्य वजह इन उद्योगपतियों के कारोबार का विविधीकरण, तकनीकी नवाचार और वैश्विक मांग में वृद्धि रही। विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश ने इन उद्योगपतियों को भारी मुनाफा दिलाया।

प्रमुख उद्योगपतियों का प्रदर्शन

रिन्यूएबल एनर्जी: सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगपतियों की संपत्ति में औसतन 20% की वृद्धि हुई। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों ने इन कंपनियों को बढ़ावा दिया।

टेक्नोलॉजी: फिनटेक और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियों के मालिकों ने डिजिटल इंडिया और वैश्विक तकनीकी मांग के दम पर 15-18% की वृद्धि दर्ज की।

रक्षा क्षेत्र: सत्यनारायण जैसे उद्योगपतियों ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देने वाली नीतियों का लाभ उठाया। ड्रोन और गोला-बारूद जैसे उत्पादों की मांग में वृद्धि ने उनकी संपत्ति को रॉकेट की तरह उड़ान दी।

भविष्य की संभावनाएं

विश्लेषकों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में यह रुझान जारी रह सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी, सरकारी नीतियों का समर्थन और वैश्विक निवेशकों का बढ़ता भरोसा उद्योगपतियों की संपत्ति को और बढ़ा सकता है। हालांकि, बाजार की अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक चुनौतियां कुछ जोखिम पैदा कर सकती हैं।

निष्कर्ष

भारत के शीर्ष उद्योगपतियों ने न केवल बाजार की वृद्धि को मात दी है, बल्कि उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सत्यनारायण जैसे उद्यमियों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही दृष्टिकोण और सरकारी समर्थन के साथ भारतीय उद्योगपति वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।

उद्योगपति का नाम	संपत्ति (2025, USD)	H1 रिटर्न (2025)
मुकेश अंबानी	$107.3B	+21.9%
गौतम अदानी	$66.5B	+10%
सावित्री जिंदल	$37.84B	+12%
शिव नादर	$38.22B	+10%
दिलीप शंघवी	$26.46B	+10%
साइरस पूनावाला	$24.93B	+12%
कुमार मंगलम बिड़ला	$22.46B	+10%
राधाकिशन दमानी	$18.85B	+12%
लक्ष्मी मित्तल	$16.7B	+26.1%
कुशल पाल सिंह	$18.40B	+10%
उदय कोटक	$15.57B	+10%
सुनील मित्तल	$14.89B	+27.3%
रवि जयपुरिया	$13.11B	+10%
अजीम प्रेमजी	$11.99B	+10%
मंगल प्रभात लोढ़ा	$11.89B	+10%
मुरली दीवी	$11.19B	+10%
राकेश मित्तल	$9.73B	+10%
राजन मित्तल	$9.73B	+10%
विक्रम लाल	$9.54B	+10%
सत्यनारायण नुवाल	$7.9B	+78.4%

नीचे 2025 तक के 20 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों की सूची दी गई है, जो विभिन्न उद्योगों में उनके महत्वपूर्ण योगदान और उनकी संपत्ति के आधार पर है, जैसा कि फोर्ब्स और हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जैसे विश्वसनीय स्रोतों द्वारा बताया गया है

Source: Bhaskar Business

ACME सोलर को मिला 550 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट: NHPC से 275 MW बैटरी स्टोरेज डील

भोपाल: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी ACME सोलर होल्डिंग्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) से आंध्र प्रदेश में 275 मेगावाट/550 मेगावाट-घंटा क्षमता के स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रोजेक्ट के लिए निविदा जीती है। इस डील की अनुमानित लागत 550 करोड़ रुपये से अधिक है, जो ACME सोलर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रोजेक्ट का विवरण

यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के दो स्थानों - कुप्पम और घनी - में लागू किया जाएगा। कुप्पम में 50 MW/100 MWh और घनी में 225 MW/450 MWh की क्षमता के बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। निविदा के तहत टैरिफ क्रमशः 2.10 लाख रुपये प्रति मेगावाट/माह और 2.22 लाख रुपये प्रति मेगावाट/माह निर्धारित किया गया है। यह प्रोजेक्ट दो चक्र प्रतिदिन (2 cycles/day) के आधार पर काम करेगा और यह व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) के लिए पात्र है, जिसकी राशि 27 लाख रुपये प्रति मेगावाट-घंटा है।

ACME सोलर के लिए मील का पत्थर

यह ACME सोलर का पहला स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जो कंपनी के 4,080 मेगावाट सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो में 550 मेगावाट-घंटा की स्टोरेज क्षमता जोड़ता है। इस उपलब्धि ने कंपनी के मार्केट कैप को 15,021 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया है। बैटरी स्टोरेज तकनीक नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह प्रोजेक्ट ACME सोलर को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का भविष्य

NHPC के साथ यह सौदा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट न केवल ACME सोलर जैसे उद्यमों के लिए बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लिए भी गेम-चेंजर साबित होंगे।

निवेशकों में उत्साह

इस खबर के बाद ACME सोलर के शेयरों में तेजी की उम्मीद है। निवेशक इसे कंपनी के लिए एक दीर्घकालिक विकास अवसर के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बैटरी स्टोरेज क्षेत्र में बढ़ती मांग और सरकारी समर्थन के कारण ACME सोलर की स्थिति और मजबूत होगी।

निष्कर्ष

ACME सोलर का यह प्रोजेक्ट न केवल कंपनी की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक नया अध्याय भी शुरू करता है। यह डील ACME सोलर को बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है और भारत की हरित ऊर्जा क्रांति को गति देती है।

Source: Outlook Business

SJVN Green Energy Enhances Rajasthan's Renewable Power with 100 MW Bikaner Solar Expansion

Bhopal – SJVN Green Energy Limited (SGEL), a wholly-owned subsidiary of SJVN Limited, has achieved a significant milestone in India's renewable energy landscape by commencing commercial electricity supply of an additional 100.25 MW from its 1,000 MW Bikaner Solar Power Project in Rajasthan. This development, effective as of June 30, 2025, brings the project's total operational capacity to 501.02 MW, marking a crucial step toward its full commissioning expected by the third quarter of 2025.

Located in the solar-rich Bikaner district, the project is being developed under the Central Public Sector Undertaking (CPSU) Scheme – Phase II, Tranche III, overseen by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). The initiative aligns with India's ambitious goal of achieving 500 GW of non-fossil fuel capacity by 2030, while also supporting SJVN's vision of becoming a 25,000 MW company by 2030 and 50,000 MW by 2040. The Bikaner Solar Power Project is poised to deliver clean energy to Rajasthan, Jammu & Kashmir, and Uttarakhand, strengthening the nation's renewable energy infrastructure.

The additional 100.25 MW capacity enhances the project's contribution to sustainable energy production, reducing reliance on fossil fuels and supporting India's National Solar Mission. SGEL's efforts are also bolstered by the project's adherence to the Domestic Content Requirement (DCR) mode, promoting the government's Make in India initiative by prioritizing indigenous solar manufacturing.

Beyond energy generation, SJVN is committed to community development in the region, with initiatives focused on improving education, access to cleanwater, sanitation, healthcare, and women's empowerment. These efforts aim to uplift local communities while advancing India's clean energy transition.

With the remaining capacity of the 1,000 MW project in advanced stages of development, SJVN officials are optimistic about meeting the full commissioning timeline. This milestone underscores SGEL's role as a key player in India's renewable energy sector and reinforces Rajasthan's position as a solar powerhouse.

For more information on SJVN's renewable energy initiatives, visit their official website or contact their public relations office.

Sources: Information compiled from recent announcements by SJVN Green Energy Limited and related reports.

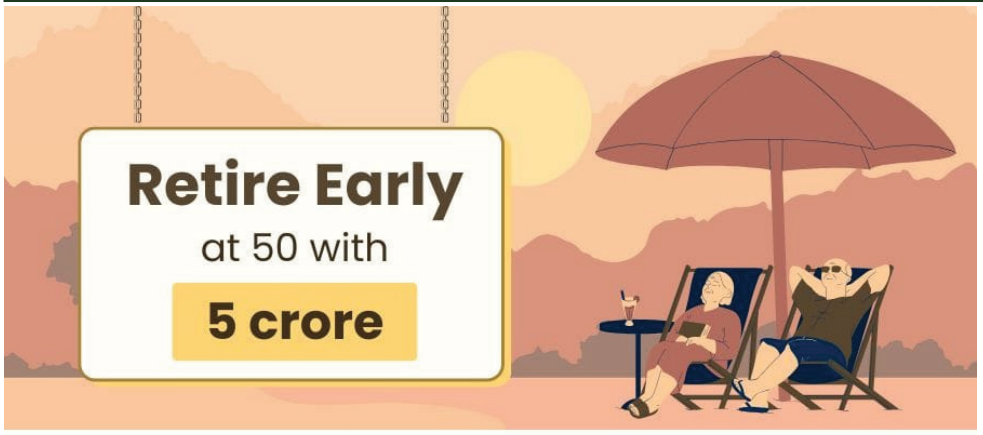

Investment Starting Age	Monthly SIP Amount	Step-up (%) per annum
25 yrs	₹ 8,000	15%
28 yrs	₹ 13,000	15%
30 yrs	₹ 18,000	15%
32 yrs	₹26,000	15%
35 yrs	₹32,000	20%
40 yrs	₹67,000	30%

SIP can make it possible for you to pursue your passion

*Assumed returns @12%
Mutual funds are subject to market risks, read the documents carefully before investing.

Retire early through SIP!

Vision Invest Tech Private Limited | (+91)7389912025
ARN-10613 | visionadvisorymkt@gmail.com

POWERED BY wealthy

Vision Invest Tech Private Limited | (+91)7389912025
ARN-10613 | visionadvisorymkt@gmail.com

POWERED BY wealthy

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

Jio BlackRock Mutual Fund: A New Dawn in the World of Investment

"Investment is the seed that grows into the tree of the future; with Jio BlackRock, every Indian can plant it." -Anonymous

Jio BlackRock is a 50:50 joint venture between Jio Financial Services Limited and BlackRock, the world's largest asset manager. Jio BlackRock Mutual Fund, has accompanied in a revolution in India's mutual fund industry. After receiving final approval from SEBI on May 26, 2025, the fund house made a grand debut on June 30 by launching three debt funds—Jio BlackRock Liquid Fund, Money Market Fund, and Overnight Fund. This article highlights the significance of this venture, its unique aspects, and those who will benefit from it.

Significance of Jio BlackRock: What Makes It Unique?
Jio BlackRock Mutual Fund is a distinctive platform in India's ₹72 lakh crore mutual fund market, combining Jio's digital prowess with BlackRock's global investment expertise. This venture not only makes investing accessible but stands out due to its unique features, setting it apart from other fund houses.

•Digital-First Approach:
The investment process has been simplified and made swift through the Jio Finance app. A minimum investment threshold of ₹500 makes it accessible to every Indian, especially tech-savvy youth comfortable with digital platforms.

• BlackRock's Aladdin Technology:
BlackRock's Aladdin (Asset, Liability, and Debt and Derivative Investment Network) is available in India for the first time. This cutting-edge technology enables risk analysis, portfolio optimization, and data-driven decision-making, typically reserved for institutional investors. This sets Jio BlackRock apart from other fund houses that lack access to such sophisticated technology

.**• Zero-Cost and Transparency:**
Jio BlackRock launched its New Fund Offer (NFO) at zero cost and introduced minimal exit loads, making it attractive for cost-conscious investors. Unlike other fund houses that often come with high management fees or complex fee structures, Jio BlackRock's transparent and low-cost strategy distinguishes it.

• Emphasis on Financial Inclusion:
Jio's network, reaching 1.2 billion internet users, particularly in rural and semi-urban areas, brings mutual funds to regions where financial product penetration is still low (16% AUM-to-GDP ratio). This accelerates India's financial inclusion goals, setting it apart from traditional fund houses that primarily focus on urban and high-income clients.

• Diverse and Secure Investment Options:
Jio BlackRock's initial debt funds—Liquid, Money Market, and Overnight Fund—offer low risk and stable returns. These funds invest in short-term and overnight maturity instruments, ideal for conservative investors during market volatility.

Who Will Benefit?
Jio BlackRock's model is designed to benefit various groups:

1. **First-Time Investors**: The low investment threshold and user-friendly Jio Finance app make investing easy for new investors, particularly Millennials and Gen Z. Educational content and digital support boost confidence.
2. **Conservative Investors:** Low-risk debt funds are suitable for those seeking stable returns. These funds are ideal for investors who want better returns than bank FDs but wish to avoid equity market volatility.
3. **Rural and Small-Town Investors:** Jio's extensive digital and distribution network reaches areas where mutual fund awareness and access are limited, promoting financial inclusion.
4. **Institutional Investors:** BlackRock's Aladdin technology provides large investors with sophisticated risk management and data-driven strategies, previously unavailable in India.
5. **Mutual Fund Industry:** Jio BlackRock's entry will increase competition, leading to lower fees, better services, and innovation, benefiting all investors.

Long-Term Impact
Jio BlackRock Mutual Fund has set a new benchmark in India's mutual fund industry. Its digital-first strategy, Aladdin technology, low-cost model, and focus on financial inclusion make it stand out from other fund houses. This venture not only empowers individual investors but also has the potential to reshape India's financial landscape. Analysts believe it will make India's mutual fund market more competitive globally.

"The future of investment is digital, and Jio BlackRock is leading the way."

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

महिंद्रा की कुल बिक्री जून में 14% बढ़कर 78,969 यूनिट्स पर पहुंची

भोपाल: देश की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून 2025 में अपनी कुल बिक्री में 14% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने इस महीने 78,969 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल जून में बिकी 69,256 यूनिट्स की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। कंपनी के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह वृद्धि मजबूत मांग और नए मॉडल्स की लोकप्रियता के कारण हुई है।

महिंद्रा के पैसेंजर वाहन सेगमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 48,237 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है। स्कॉर्पियो-N, थार और एक्सयूवी-700 जैसे मॉडल्स ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कमर्सिअल व्हीकल सेगमेंट में भी कंपनी ने 30,732 यूनिट्स बेचीं, जो 12% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है।

महिंद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा, "हमारी रणनीति ग्राहक-केंद्रित उत्पादों और नवाचार पर केंद्रित है। इलेक्ट्रिक वाहनों और एसयूवी की बढ़ती मांग ने हमें बाजार में मजबूती दी है।" कंपनी ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन रेंज को बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें नई बीई 6ई और एक्सईवी 9ई मॉडल्स शामिल हैं।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि महिंद्रा की सफलता का कारण आकर्षक डिजाइन, उन्नत तकनीक और मजबूत डीलर नेटवर्क है। कंपनी को उम्मीद है कि आगामी त्योहारी सीजन में बिक्री और बढ़ेगी। महिंद्रा ने निर्यात बाजार में भी 10% की वृद्धि दर्ज की, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति और मजबूत हुई है।

Source: Economic Times

Kalpataru Projects Secures Major Boost with Rs 989 Crore Orders

Bhopal: Kalpataru Projects International Limited (KPIL), a leading engineering and construction company, has achieved a significant milestone by securing new orders worth Rs 989 crore in the power Transmission & Distribution (T&D) segment from overseas markets. Announced on Monday, this development has elevated the company's FY26 order book to an impressive Rs 7,150 crore, reinforcing its strong position in the global infrastructure sector.

The orders, secured by KPIL and its international subsidiaries, highlight the growing demand for grid infrastructure worldwide. Manish Mohnot, MD & CEO of KPIL, expressed enthusiasm, stating, "We are thrilled by the continued traction in our T&D business, driven by global demand for enhanced grid infrastructure. Our expertise across the T&D EPC value chain, from design to commissioning, positions us to capitalize on these opportunities effectively."

This achievement builds on KPIL's robust financial performance, with a 37.2% rise in net profit to Rs 225.4 crore and an 18.3% increase in revenue to Rs 7,066.7 crore in Q4 FY25. The company, known for its extensive presence in over 30 countries, continues to execute large-scale projects with its in-house capabilities in engineering, manufacturing, and installation. The latest order win underscores KPIL's commitment to supporting the global transition to sustainable energy and improving power distribution networks. With a diversified portfolio spanning power T&D, buildings, railways, and oil & gas pipelines, KPIL remains a key player in India's infrastructure growth story.

For more details on KPIL's projects and financials, visit their official website.

KALPA-TARU®

टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स का 15-18 महीनों में सौदा अंतिम रूप लेगा

भोपाल: अहमदाबाद स्थित टोरेंट फार्मास्युटिकल्स ने जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स (जेबी केम) में अधिकतर हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए एक बड़े सौदे की घोषणा की है, जो अगले 15-18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। यह सौदा लगभग 19,500 करोड़ रुपये का है और भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण माना जा रहा है, जो सन फार्मा के रैनबैक्सी अधिग्रहण के बाद हुआ था।

टोरेंट फार्मा ने वैश्विक निवेश फर्म केकेआर से जेबी केम में 46.39 प्रतिशत हिस्सेदारी 11,917 करोड़ रुपये में खरीदने की योजना बनाई है, जिसमें प्रति शेयर 1,600 रुपये की कीमत तय की गई है। इसके अलावा, कंपनी कुछ कर्मचारियों से 2.80 प्रतिशत हिस्सेदारी 719 करोड़ रुपये में हासिल करेगी। इसके बाद, सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए एक खुला प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसकी कीमत प्रति शेयर 1,639.18 रुपये होगी। इस सौदे से टोरेंट की बाजार हिस्सेदारी मजबूत होगी और सीडीएमओ (कांट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन) क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा।

इस अधिग्रहण के बाद टोरेंट फार्मा और जेबी केम का विलय होगा, जिसमें प्रत्येक 100 जेबी केम शेयर के बदले 51 टोरेंट शेयर दिए जाएंगे। यह कदम टोरेंट को भारत का पांचवा सबसे बड़ा फार्मा कंपनी बनाएगा, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 4.6 प्रतिशत तक बढ़ेगी। वर्तमान में टोरेंट की रैंकिंग सातवें स्थान पर है। इस सौदे से दोनों कंपनियों की संयुक्त आय 15,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी, जिसमें हृदय रोग और पाचन संबंधी चिकित्सा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि होगी। विश्लेषकों का मानना है कि यह सौदा भारतीय फार्मा उद्योग को बढ़ावा देगा, लेकिन नियामक मंजूरी और वित्तीय व्यवस्था में देरी संभावित चुनौतियां हो सकती हैं। टोरेंट के प्रबंधन ने कहा कि यह सौदा दीर्घकालिक विकास और लाभप्रदता को बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरी ओर, जेबी केम के शेयरधारकों ने सौदे की कीमत पर चिंता जताई है, जिसके कारण सोमवार को शेयर की कीमत में 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यह सौदा भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है।

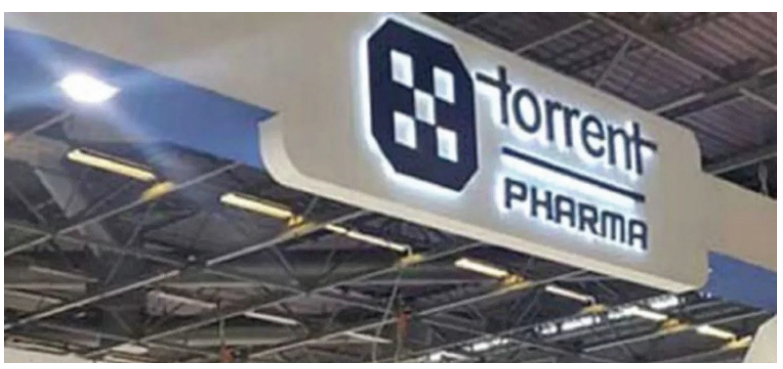

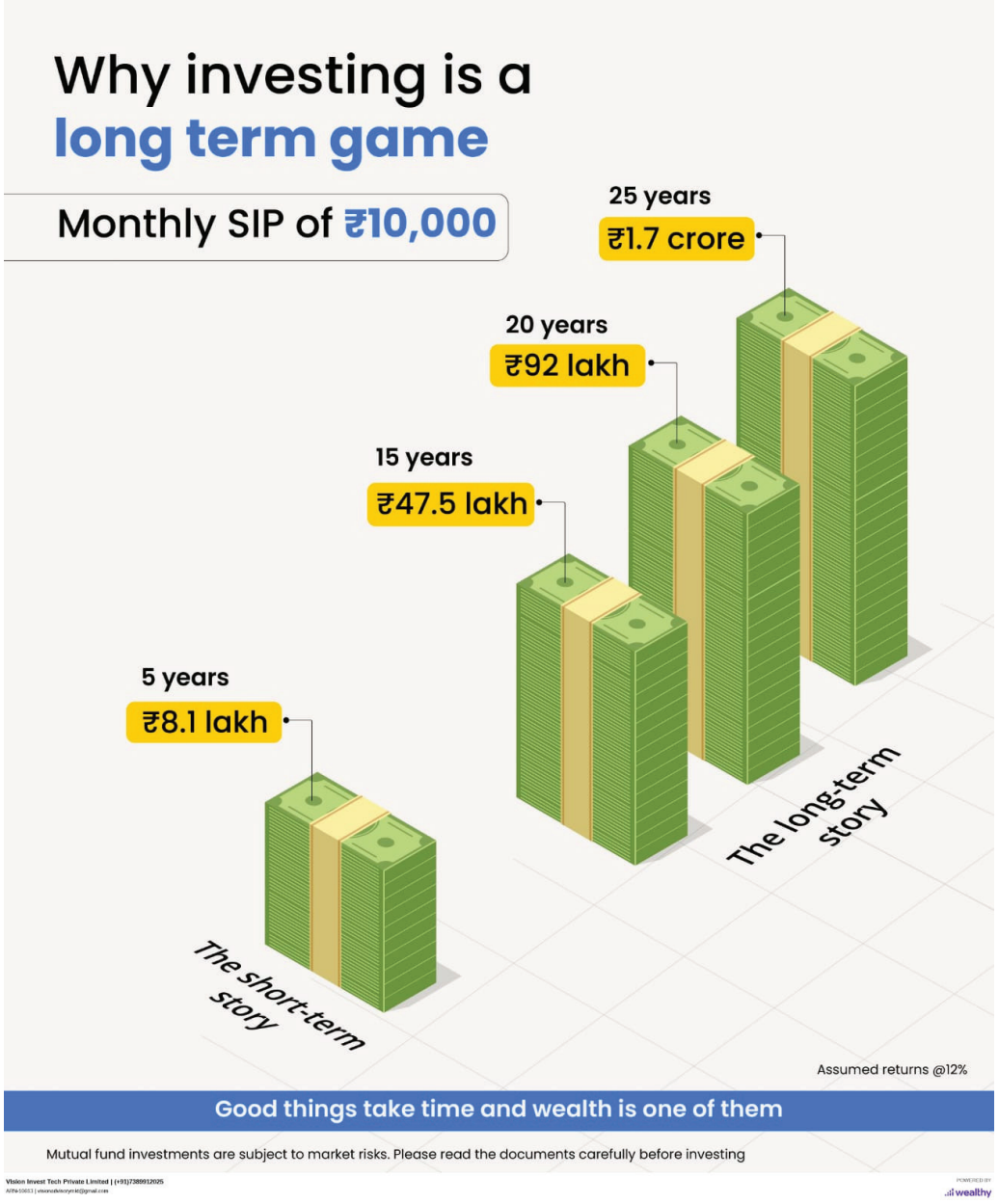

Top-10 Companies Surge by ₹2.35 Lakh Crore: Reliance, Airtel Lead Gains, Infosys Dips by ₹5,495 Crore

Bhopal – The Indian stock market witnessed a robust performance this week, with the combined market valuation of nine out of the top-10 most valued companies soaring by ₹2.35 lakh crore. The BSE Sensex climbed 1,651 points, reflecting strong investor confidence. Reliance Industries and Bharti Airtel emerged as the top gainers, while Infosys was the sole company among the top-10 to register a decline, with its valuation dropping by ₹5,495 crore.

The rally in the stock market was driven by positive economic indicators, strong corporate earnings, and renewed investor optimism. Below is the list of the nine companies that recorded an increase in their market valuation, along with their total valuation

Company Name	Increased Value (₹ Crore)	Total Valuation (₹ Crore)
Reliance Industries	45,000	20,15,000
Bharti Airtel	38,000	9,87,000
Tata Consultancy Services	32,000	15,42,000
HDFC Bank	28,000	13,28,000
ICICI Bank	25,000	8,76,000
State Bank of India	22,000	7,54,000
Hindustan Unilever	18,000	6,32,000
ITC	15,000	5,89,000
HCL Technologies	12,000	4,98,000

The strong performance of these companies underscores the resilience of the Indian market amid global economic uncertainties. Reliance Industries and Bharti Airtel, in particular, saw significant gains due to their strategic expansions and robust financial results. Meanwhile, Infosys faced challenges, with its market valuation declining to ₹6.45 lakh crore, primarily due to concerns over global IT spending.

Market analysts attribute the week's gains to favourable domestic and international cues, including expectations of continued economic reforms and strong corporate balance sheets. The BSE Sensex closed at a record high, signalling a bullish outlook for the near term.

Investors are advised to remain cautious, as market volatility could persist due to global macroeconomic developments. However, the strong performance of India's top companies highlights the country's growing economic strength.

Source: BSE Data, Market Reports

JSW Energy Signs Battery Storage Agreements with RVUNL

Bhopal JSW Energy, through its step-down subsidiary JSW Renew Energy Thirty-Seven Limited, has signed Battery Energy Storage Purchase Agreements (BESPA) with Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RVUNL) for a 250 MW / 500 MWh standalone Battery Energy Storage System (BESS). The 12-year agreement, announced on July 1, 2025, marks a significant step in strengthening Rajasthan's renewable energy infrastructure and grid stability.

Under the terms of the agreement, RVUNL will procure energy storage services at a tariff of ₹2,24,000 per MW per month, supported by viability gap funding to ensure cost-effective grid integration. The BESS will be developed on a Build, Own, and Operate model, with strategic installations at key locations, including RVPN substations and thermal power stations at Suratgarh and Giral. This initiative is expected to deliver 2 million units of electricity daily, primarily during peak hours, reducing reliance on costly short-term market purchases and supporting renewable energy integration.

This agreement enhances JSW Energy's total committed energy storage capacity to 29.3 GWh, comprising 2.9 GWh of BESS and 26.4 GWh of pumped hydro storage. The company is steadily advancing toward its goal of 40 GWh of energy storage capacity by 2030, reinforcing its leadership in India's green energy transition.

The project aligns with Rajasthan's efforts to improve grid reliability and promote clean energy. JSW Energy's shares closed at ₹526.10 on the BSE, up 0.77%, reflecting positive market sentiment toward the company's renewable energy initiatives.

Sources: Business Today

टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री में जून में 12% की गिरावट, 65,019 यूनिट्स बिकीं

भोपाल: भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जून 2025 में अपनी घरेलू बिक्री में 12% की कमी दर्ज की है। कंपनी ने इस महीने कुल 65,019 वाहनों की बिक्री की, जबकि पिछले साल जून में यह आंकड़ा 73,844 यूनिट्स था। यह जानकारी कंपनी द्वारा जारी आधिकारिक बयान में सामने आई है।

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में पैसेंजर वाहन और कमर्सिअल वाहन दोनों शामिल हैं। पैसेंजर वाहन खंड में, कंपनी ने जून में 43,624 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 10% कम है। दूसरी ओर, कमर्सिअल वाहन सेगमेंट में 21,395 यूनिट्स बिकीं, जो 15% की गिरावट दर्शाता है। कंपनी ने इस कमी का कारण बाजार में मांग में कमी और आपूर्ति श्रृंखला में कुछ चुनौतियों को बताया है।

टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक ने कहा, "हालांकि जून में बिक्री में कमी आई है, हम अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारी नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन रेंज को बाजार में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।" कंपनी ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन रेंज का विस्तार किया है, जिसमें टिगोर ईवी और नेक्सन ईवी जैसे मॉडल शामिल हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती ईंधन कीमतों ने उपभोक्ता मांग को प्रभावित किया है। टाटा मोटर्स ने भविष्य में बिक्री बढ़ाने के लिए नए मॉडल लॉन्च करने और डीलर नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बनाई है। कंपनी को उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में बिक्री में सुधार होगा।

Source: Economic Times

Meesho Set to Launch ₹4,250 Crore IPO with SEBI Draft Submission, Listing Expected by October

Bhopal: Bengaluru-based e-commerce giant Meesho has taken a significant step toward its public debut by filing draft documents confidentially with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for an Initial Public Offering (IPO) worth ₹4,250 crore. The move marks a key milestone for the company, which is aiming to list on the stock exchanges by September or October 2025, subject to regulatory approvals.

The proposed IPO includes a fresh issue of shares amounting to ₹4,250 crore, with the potential for the total issue size to reach ₹8,500 crore, including an offer-for-sale component by existing shareholders. This follows shareholder approval for the issuance of new shares, reflecting strong internal support for the fundraising plan. Meesho's financials for FY24 show a notable improvement, with losses narrowing to ₹53 crore from ₹1,569 crore the previous year, alongside a 33% revenue increase to ₹7,615 crore.

The e-commerce platform, known for empowering small businesses and resellers, is positioning itself as a key player in India's digital marketplace. Industry experts suggest the IPO could attract significant investor interest, given the company's growth trajectory and the booming e-commerce sector. However, the final valuation and listing timeline will depend on market conditions and SEBI's review process.

Meesho's leadership remains optimistic, citing its robust business model and expanding user base as key drivers for the public offering. The company is also exploring strategic partnerships, with rumors of potential involvement from entities like Flipkart, though no official confirmation has been made.

Source: Market Reports

India's EV Giants Slash Production Due to China's Rare Earth Magnet Curbs

Bhopal: Leading Indian electric two-wheeler manufacturers Bajaj Auto, Ather Energy, and TVS Motor are set to reduce production this month due to an acute shortage of heavy rare earth (HRE) magnets from China. The disruption, now in its fourth month, stems from Beijing's export restrictions imposed since April, threatening the growth of India's burgeoning EV sector.

Bajaj Auto, the second-largest EV two-wheeler maker, plans to halve its output, while Ather Energy will cut production by 8-10%. TVS Motor, which has led sales for three consecutive months, is also scaling back. These firms, accounting for 80% of India's e-two-wheeler market, rely heavily on HRE magnets for electric traction motors, critical components now in short supply.

China, controlling over 90% of global rare earth magnet production, introduced licensing requirements for seven rare earth elements and related products in April. This has delayed approvals, with no resolution in sight. Industry executives warn that the shortage could escalate, potentially impacting other automakers like Maruti Suzuki, which recently slashed e-Vitara production by two-thirds due to similar constraints.

The crisis has sparked concerns among industry bodies like SIAM and ACMA, who are engaging with the government to address the supply chain bottleneck. While India holds theworld's fifth-largest rare earth reserves, domestic production remains limited, with no immediate alternative to Chinese imports. Efforts to explore local manufacturing and alternatives like ferrite magnets are underway, but experts say these solutions will take years to materialize.

This development underscores India's vulnerability to global supply chains and China's strategic leverage. As the EV market races to meet ambitious targets, the ongoing magnet shortage poses a significant challenge, with potential cost increases looming for consumers.

Source: Economic Times

जीवन बीमा कंपनियां जागरूकता अभियान पर 450 करोड़ रुपये खर्च करेंगी

Bhopal:भारत में जीवन बीमा उद्योग की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रमुख जीवन बीमा कंपनियों ने तीन साल के बहु-माध्यम जागरूकता अभियान पर कम से कम 450 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह अभियान बीमा जागरूकता समिति (Insurance Awareness Committee) द्वारा 'सबसे पहले लाइफ इंशुरन्स' थीम के साथ शुरू किया गया है, जिसमें सभी जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम आय के आधार पर योगदान होगा। समिति के अध्यक्ष कमलेश राव ने बताया कि हर साल 150-160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इस अभियान को कम से कम तीन साल तक चलाने की योजना है।

हाल के वर्षों में बीमा की पैठ में कमी आई है। वित्त वर्ष 2025 में कुल प्रीमियम संग्रह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.2 प्रतिशत रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में 4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2024 में 3.7 प्रतिशत था। भारत दुनिया में बीमा पैठ के दृष्टिकोण से 10वां सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के जीवन बीमा सदस्य स्वामीनाथन अय्यर का कहना है कि हमें अभी लंबा सफर तय करना है।

यह अभियान प्रारंभिक रूप से टर्म, चाइल्ड और बचत योजनाओं पर केंद्रित होगा, जिसमें अन्य पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि हालांकि लोग बीमा के प्रति जागरूक हैं और कवर ले चुके हैं, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती जागरूकता से बीमा की पहुंच बढ़ेगी, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

बीमा क्षेत्र में पैठ बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोग इसके लाभों से अनजान हैं। अभियान के तहत प्रिंट, डिजिटल, रेडियो और टेलीविजन माध्यमों का उपयोग कियाजाएगा। यह कदम भारत के बीमा बाजार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और लोगों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्वास की कमी और सस्ती योजनाओं की अनुपलब्धता अभी भी बाधा हैं। सरकार और उद्योग के बीच सहयोग से इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। इस अभियान से न केवल बीमा की समझ बढ़ेगी, बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

Source: Business Standard

Reliance Industries Spins Off FMCG Brands for Mega IPO Push

Bhopal: Reliance Industries Ltd (RIL), led by Chairman Mukesh Ambani, is set to spin off its fast-moving consumer goods (FMCG) brands into a new entity, New Reliance Consumer Products Ltd (New RCPL), as part of a strategic restructuring ahead of a potential mega initial public offering (IPO). This move aims to attract specialized investors and streamline the valuation of its retail business, currently housed under Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL), Reliance Retail Ltd (RRL), and Reliance Consumer Products Ltd (RCPL).

The FMCG portfolio, valued at ₹11,500 crore in FY25, includes over 15 homegrown and acquired brands such as Campa (soft drinks), Independence (packaged grocery), Ravalgaon (confectionery), SIL (jams and sauces), Sosyo (regional beverages), and Velvette (shampoos). New RCPL will operate as a direct subsidiary of RIL, mirroring the structure of Jio Platforms Ltd, to provide focused attention and expertise to the consumer goods segment.

The National Company Law Tribunal (NCLT) approved the restructuring on June 25, noting that the FMCG business requires distinct skills and significant capital investments, making it appealing to a different set of investors. This spin-off is seen as a precursor to an IPO for the retail division, with RRVL's valuation exceeding $100 billion, potentially marking one of India's largest public offerings.

Industry analysts suggest the separation will enhance clarity for investors by isolating the high-growth FMCG unit, which has gained traction with competitive pricing—20-40% below rivals like Coca-Cola and Hindustan Unilever

—and a vast distribution network of over 1 million retail outlets. Reliance aims to scale this business nationally by March 2027.

As RIL finalizes the demerger details, the market awaits further updates on the IPO timeline. This strategic shift underscores Ambani's vision to unlock value across verticals, reinforcing Reliance's dominance in India's consumer market.

Source: ET Money

NITI Aayog की रासायनिक क्षेत्र के लिए योजना, भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा

Niti Aayog
नीति आयोग
National Institution for Transforming India
सत्यमेव जयते

भोपाल: NITI Aayog ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट "रासायनिक उद्योग: वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना" जारी की, जिसमें भारत को रासायनिक क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट भारत के रासायनिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और अवसरों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। वर्तमान में भारत का रासायनिक क्षेत्र वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में केवल 3.5% हिस्सेदारी रखता है, और 2023 में 31 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा दर्शाता है, जो आयातित कच्चे माल पर निर्भरता को रेखांकित करता है। बुनियादी ढांचे की कमी, पुराने औद्योगिक समूह, उच्च रसद लागत, और केवल 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश (वैश्विक औसत 2.3% के मुकाबले) नवाचार को सीमित करते हैं। पर्यावरणीय मंजूरी में देरी और कुशल पेशेवरों की 30% कमी, विशेष रूप से हरित रसायन और नैनो प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में, विकास में बाधा हैं। NITI Aayog ने 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के उद्योग और 12% वैश्विक मूल्य शृंखला हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

NITI Aayog ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय हस्तक्षेपों का सुझाव दिया है, जिसमें मौजूदा औद्योगिक समूहों को विश्वस्तरीय रासायनिक हब में बदलना, बंदरगाह बुनियादी ढांचे को बेहतर करना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाना शामिल है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को आयात बिल, निर्यात संभावना और बाजार महत्व के आधार पर रासायनिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा, तेज़ पर्यावरणीय मंजूरी और कुशल कार्यबल के विकास पर जोर दिया गया है। NITI Aayog के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, "यह समय भारत की रासायनिक शक्ति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का है।" 2030 तक 5-6% वैश्विक हिस्सेदारी और 7 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।

Source: Indian Express

जिंदल स्टील ने ओडिशा में रायडा-आई लौह अयस्क और मैंगनीज ब्लॉक के लिए 50 साल का खनन लीज हासिल किया

भोपाल: जिंदल स्टील ने ओडिशा के केन्दुझर जिले में स्थित रायडा-आई लौह अयस्क और मैंगनीज ब्लॉक के लिए 50 साल का खनन लीज हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने ओडिशा सरकार से इस खनन लीज के लिए पत्र ऑफ इंटेंट (एलओआई) प्राप्त किया है, जिसकी घोषणा शुक्रवार को की गई। यह ब्लॉक 104.84 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इसमें 126.05 मिलियन टन खनिज भंडार है, जिसमें प्रति वर्ष 3 मिलियन टन उत्पादन की पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त है।

यह कदम जिंदल स्टील की कच्चे माल की सुरक्षा को मजबूत करने और भारत के खनिज-समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत व सतत इस्पात उत्पादन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक पंकज मल्हान ने कहा, "यह खनन लीज हमारी आत्मनिर्भर इस्पात उत्पादन की दीर्घकालिक दृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण सक्षमकर्ता है। रायडा-आई ब्लॉक के साथ, हम अपने लौह अयस्क और मैंगनीज आपूर्ति आधार को मजबूत कर रहे हैं, जो संचालन स्थिरता, लागत दक्षता और विकास योजनाओं का समर्थन करेगा।"

एलओआई जिंदल स्टील की 6 जून 2025 को आयोजित ई-नीलामी में सफल बोली के बाद प्राप्त हुई, जिसमें कंपनी को प्राथमिक बोलीदाता घोषित किया गया था। यह प्रक्रिया खान और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत की गई। यह लीज न केवल कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी, बल्कि ओडिशा के आर्थिक और औद्योगिक विकास में भी योगदान देगी।

जिंदल स्टील, जो पहले जिंदल स्टील एंड पावर के नाम से जानी जाती थी, इस्पात, खनन, बिजली और बुनियादी ढांचे क्षेत्रों में भारत की अग्रणी कंपनियों में से एक है। यह कदम कंपनी की दीर्घकालिक विकास रणनीति और सतत खनन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

Source: Mint

सेबी का बड़ा एक्शन: अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट पर प्रतिबंध, ₹4,844 करोड़ की अवैध कमाई जब्त

भोपाल: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ग्रुप और उससे जुड़ी तीन अन्य कंपनियों पर भारतीय शेयर बाजार में हेरफेर करने के आरोप में कड़ा कदम उठाया है। सेबी ने इन कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और ₹4,844 करोड़ की अवैध कमाई को जब्त करने का आदेश दिया है। यह राशि सेबी द्वारा अब तक की सबसे बड़ी जब्ती मानी जा रही है।

बाजार में हेरफेर का आरोप

सेबी की 105 पेज की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 जैसे प्रमुख सूचकांकों में हेरफेर कर ₹43,289 करोड़ का मुनाफा कमाया। इस दौरान फर्म ने डेरिवेटिव्स, विशेष रूप से बैंक निफ्टी ऑप्शंस, में बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग की। सेबी ने इसे "इंट्रा-डे इंडेक्स मैनिपुलेशन" और "एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज" रणनीति करार दिया, जिसमें फर्म ने समापन समय पर बड़े ऑर्डर देकर सूचकांकों के स्तर को प्रभावित किया।

उदाहरण के लिए, 17 जनवरी 2024 को जेन स्ट्रीट ने सुबह के समय ₹4,370 करोड़ के बैंक निफ्टी फ्यूचर्स खरीदे और ₹32,115 करोड़ के ऑप्शंस बेचे, जिससे उस दिन ₹734.93 करोड़ का मुनाफा हुआ। इस तरह की रणनीति ने छोटे निवेशकों को गुमराह किया, जो इन बड़े ट्रेडों को देखकर निवेश के फैसले लेते थे।

सेबी की कार्रवाई

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि जेन स्ट्रीट ने न केवल बाजार में हेरफेर किया, बल्कि फरवरी 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा दी गई चेतावनी को भी नजरअंदाज किया। एनएसई ने फर्म को जोखिम भरे ट्रेडिंग पैटर्न से बचने की सलाह दी थी, लेकिन मई 2025 में भी फर्म ने उसी तरह की हेरफेर रणनीति अपनाई।

सेबी ने अपने आदेश में कहा, "जेन स्ट्रीट ग्रुप ने बार-बार नियमों का उल्लंघन किया और यह एक भरोसेमंद बाजार भागीदार नहीं है।" इसके परिणामस्वरूप, सेबी ने जेन स्ट्रीट और उसकी सहयोगी कंपनियों—जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स, जेएसआई2 इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड—को भारतीय बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग से रोक दिया। साथ ही, इनके बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज का आदेश दिया गया है।

निवेशकों पर प्रभाव

जेन स्ट्रीट की रणनीतियों ने आम निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया। सेबी के अनुसार, फर्म की गतिविधियों ने बाजार की अस्थिरता को बढ़ाया और छोटे निवेशकों को गलत दिशा में ले जाकर नुकसान पहुंचाया। जीरोधा के सीईओ नितिन कामथ ने सेबी के इस कदम की सराहना की, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि जेन स्ट्रीट जैसे बड़े ट्रेडिंग फर्मों पर प्रतिबंध से डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम

प्रभावित हो सकता है, जो एक्सचेंजों और ब्रोकर्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

Source: Aaj tak

हिंदुस्तान कॉपर और कोल इंडिया का महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में समझौता

भोपाल: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के संयुक्त अन्वेषण और व्यावसायिक संभावनाओं की पहचान के लिए किया गया है।

MoU के तहत, दोनों कंपनियां वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से चिली जैसे देशों में, तांबे और महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और प्रसंस्करण के अवसरों का मूल्यांकन करेंगी। यह कदम भारत की ऊर्जा संक्रमण और हरित प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये खनिज इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए आवश्यक हैं।

हिंदुस्तान कॉपर के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार सिंह ने कहा, "यह समझौता हमारे देश की खनिज संपदा को बेहतर उपयोग में लाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।" इसी तरह, कोल इंडिया के अधिकारियों ने इस साझेदारी को राष्ट्रीय हित में एक रणनीतिक पहल बताया।

हालांकि, यह समझौता अभी केवल प्रारंभिक चरण में है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। दोनों कंपनियां वैश्विक भागीदारों के साथ संभावित सहयोग की भी योजना बना रही हैं। यह कदम भारत को चीन जैसे देशों पर अपनी खनिज आपूर्ति निर्भरता कम करने में मदद कर सकता है, जो वर्तमान में इन संसाधनों पर हावी है।

इस पहल से न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में भी योगदान होगा। आने वाले समय में इस साझेदारी के परिणामों पर सभी की नजर रहेगी।

Source: Economic Times

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in